

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 036/2017 (GCMS 2017/00095)	दायर दिनांक 05.10.2017	निर्णय दिनांक 11.08.2021
---	----------------------------------	------------------------------------

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये विकास अधिकारी भदेसर पंचायत समिति
भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

निगराकार

बनाम

1. प्रशान्त गिरी पिता प्रभु गिरी निवासी लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. ग्राम पंचायत लेसवा पंचायत समिति भदेसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

गैर निगराकार

--:: निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994, विरुद्ध पट्टा संख्या 078 दिनांक 04.05.2017 ग्राम पंचायत लेसवा पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज. :-

उपस्थिति :- अनिल कुमार टेलर,
(सहायक विकास अधिकारी बडीसादडी)
अनुपस्थित

निगराकार
गैर निगराकार संख्या 1, 2

--:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार प्रशान्त गिरी पिता प्रभु गिरी निवासी लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को उक्त पट्टा विधिक प्रावधानों एवं नियमों के विपरित आबादी भूमि की जानकारी के अभाव में सहवन से जारी हो गया है। उक्त जानकारी होते ही गैर निगराकार को ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा नोटिस जारी किया गया जिस पर गैर निगराकार द्वारा उक्त मूल पट्टे व पंजीयन को ग्राम पंचायत लेसवा में दिनांक 26.09.2017 को समर्पण कर पट्टे को निरस्त करने का अनुरोध



किया है। इस पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.09.2017 प्रस्ताव संख्या 1 से उक्त पट्टे एवं पंजीयन को निरस्त कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाते हुए गैर निगराकार संख्या 1 को गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 87 दिनांक 04.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर विकास अधिकारी, भदेसर के पत्रांक/पंसभ/नि0प्रा0/2017-18/1872 दिनांक 21.02.2018 से ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 11.02.2021 को गैर निगराकारान संख्या 1, 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर निगराकार संख्या 1, 2 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई।

दिनांक 11.08.2021 को निगराकार की और से अनिल कुमार टेलर, प्रतिनिधि सहायक विकास अधिकारी, भदेसर हाजिर आये एवं प्रकरण में पक्षकारान की अनुपस्थिति रिकार्ड किये जाने से बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर सहायक विकास अधिकारी भदेसर द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। अपनी बहस में सहायक विकास अधिकारी भदेसर द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा गैर निगराकार प्रशान्त गिरी पिता प्रभु गिरी निवासी लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को उक्त पट्टा विधिक प्रावधानों एवं नियमों के विपरित आबादी भूमि की जानकारी के अभाव में सहवन से जारी हो गया है। उक्त जानकारी होते ही गैर निगराकार को ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा नोटिस जारी किया गया जिस पर गैर निगराकार द्वारा उक्त मूल पट्टे व पंजीयन को ग्राम पंचायत लेसवा में दिनांक 26.09.2017 को समर्पण कर पट्टे को निरस्त करने का अनुरोध किया है। इस पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.09.2017 प्रस्ताव संख्या 1 से उक्त पट्टे एवं पंजीयन को निरस्त कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाते हुए गैर निगराकार संख्या 1 को गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 87 दिनांक 04.05.2017 निरस्त फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ सहायक विकास अधिकारी भदेसर ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।



पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम



157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये है।

157. Regularisation of old houses.-

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

- (a) For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules Rs. 100 /-
- (b) For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016]. Rs. 200/-

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। प्रावधानुसार जहाँ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण के है कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। उक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि स्थित गृहों के विनियमितीकरण किये जाने की ही क्षेत्राधिकारिता है गैर आबादी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 द्वारा प्रदान नहीं किये गये है।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा से प्राप्त मूल अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हस्तगत प्रकरण में मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक गैर निगराकार संख्या 1 के आवेदन दिनांक 02.04.2017 प्रस्तुत किया। इस पर ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा आज्ञा संख्या 2 से अन आपत्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया। आज्ञा संख्या 3 से दिनांक 07.04.2017 को 15 दिन की अन्दर मियाद का अन-आपत्ति पत्र जारी करने के विरुद्ध कार्यालय ग्राम पंचायत में किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। आपत्ति दर्ज नहीं होने से मौका पर्चा तैयार करने का अंकन किया गया है। आज्ञा संख्या 4 से बाद कार्यवाही के गैर निगराकार को पट्टा जारी किये जाने का अंकन किया गया है। उक्त



आज्ञा की सूची में आवेदित भूखण्ड के संबंध में किसी भी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है, इसके साथ ही आज्ञा की सूची में सरपंच ग्राम पंचायत लेसवा के पूरी आज्ञा की सूची पर हस्ताक्षर नहीं है। आज्ञा की सूची में किसी भी प्रकार से दिनांक की क्रमबद्धता नहीं है। पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण-पत्र का मात्र प्रारूप संलग्न किया गया है, उस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट अथवा प्रमाण पत्र जारी करने के प्रमाण में हल्का पटवारी के हस्ताक्षर/रिपोर्ट का अभाव है। हस्तगत प्रकरण में मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपत्ति मांगने का सूचना पत्र पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एवं 15 दिवस की अवधि निर्धारित की गई है। पत्रावली में संलग्न नोटिस के अवलोकन से जाहिर होता है कि नोटिस में भूमि का विवरण अंकित नहीं है, जबकि विधि अनुसार उक्त नोटिस में भूमि का विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही उक्त नोटिस पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तथा नियम 148 के उप नियम (2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त नोटिस को प्रचारित किया जाना जाहिर नहीं होता है।

वार्ड पंचों की समिति द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि रिपोर्ट में भूखण्ड के संबंध में किसी भी प्रकार का वर्णन अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के स्पष्ट रूप से अनदेखी जाहिर होती है। इसके साथ ही हमने गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 26.09.2017 का अवलोकन किया जिसमें गैर निगराकार संख्या 1 स्वयं द्वारा ही उक्त विवादित पट्टा के निरस्ती हेतु समर्पण पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं मूल पंजीकृत पट्टा पंजीयन दिनांक 11.07.2017 ग्राम पंचायत लेसवा को समर्पण किया जो कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 1 न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे है ऐसी स्थिति में निगरानी मेमों का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों, उप-नियमों एवं प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। इसके साथ ही गैर-निगराकार प्रकरण में अनुपस्थित रहे है ऐसी स्थिति में निगरानी का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति



में जाहिर आता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा पंचायत समिति भदेसर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा त्रुटि कारित की गई है। इसके साथ निगरानी पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधिनियम की धारा 97 के प्रावधानों के तहत ही विचार किया जाना है। अधिनियम की धारा 97 में अंकित प्रावधानों के अनुसरण में उक्त विवादित पट्टा संख्या 078 दिनांक 04.05.2017 की ही परीक्षण किया जाना है। विकास अधिकारी भदेसर द्वारा निगरानी में उठाये गये अन्य तथ्यों के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है। ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा संख्या 078 दिनांक 04.05.2017 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत लेसवा पंचायत समिति भदेसर द्वारा विवादित पट्टा संख्या 078 दिनांक 04.05.2017 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 078 दिनांक 04.05.2017 जो कि गैर निगराकार संख्या 1 प्रशान्त गिरी पिता प्रभु गिरी निवासी लेसवा पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी भदेसर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11.08.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़